

सफलता केवल मंजिल तक पहुँचने में नहीं, बल्कि हर दिन स्वयं को पहले से बेहतर बनाने के निरंतर प्रयास में छिपी होती है।

RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number : F.2 (P-2)
Press/2023

वर्ष 04, अंक 179, नई दिल्ली, रविवार 04 अक्टूबर 2026, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

03 पितृ पक्ष पर विशेष: पितरों के मोक्ष का सरल मार्ग है- पिण्डदान

06 नशे से सियासत तक: पंजाब की एक कड़वी कहानी

08 झारखंड हाईकोर्ट ने दाखिले की विदेशी छात्रवृत्ति रोकने पर कड़ी आपत्ति जताई

महिला सुरक्षा पर एक ऐतिहासिक विश्लेषण रिपोर्ट - परिवहन विशेष - Transport Special National Newspaper

सड़कें, सुरक्षा और महिलाएं - बदलती तस्वीर, कड़वी हकीकत - स्वतंत्रता का वादा, सुरक्षा का इम्तिहान

संविधान से सुप्रीम कोर्ट तक - मोटर वाहन अधिनियम से निर्भया फंड तक - महिला गतिशीलता केवल बुनियादी ढांचा नहीं - मौलिक अधिकार का प्रश्न है

लेखिका: पिकी कुंडू, सामाजिक परामर्शदाता

प्रस्तावना: सड़कें केवल डामर नहीं, लोकतंत्र की नसें हैं -

* जब एक छात्रा कॉलेज जाती है, * एक नर्स नाइट ड्यूटी से लौटती है, तो वह सिर्फ यात्रा नहीं कर रही, संविधान के अनुच्छेद 19(1)(घ) - सर्वत्र भ्रमण के अधिकार का प्रयोग कर रही है।

पर सवाल है, क्या राज्य ने उसे अनुच्छेद 21 - गरिमापूर्ण और सुरक्षित जीवन का अधिकार दिया ?

संवैधानिक आधार - तथ्य और अधिकांश

1. अनुच्छेद 14, 15(3) और 21: संविधान महिलाओं को समानता और विशेष संरक्षण दोनों देता है। सुप्रीम कोर्ट ने Vishaka vs State of Rajasthan (1997) और बाद में POSH Act 2013 में कहा - कार्यस्थल तक सुरक्षित पहुँचना भी कार्यस्थल की सुरक्षा का हिस्सा है। सड़क अगर असुरक्षित है तो यह अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है।

2. अनुच्छेद 19(1)(d): भारत के किसी भी कोने में भ्रमण का अधिकार। अगर कोई महिला अंधेरा, सुनसान बस स्टॉप या छेड़छाड़ के डर से शाम 6 बजे के बाद यात्रा नहीं कर पाती, तो यह अधिकार केवल कागज पर है।

न्यायिक आदेश - सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले

तथ्य 1: निर्भया के बाद की न्यायिक चेतना:

- Mukesh vs State (Nirbhaya Case) 2017: कोर्ट ने कहा - सार्वजनिक परिवहन में सुरक्षा राज्य की अनिवार्य जिम्मेदारी है, ऐच्छिक नहीं।

- Aparna Bhat vs State of MP (2021): जमानत की शर्तों में महिलाओं को अपमानित करने वाले आदेश नहीं दिए जा सकते, सड़क पर गरिमा बनी रहनी चाहिए।

परिवहन विशेष
Transport Special National Newspaper

सड़कें, सुरक्षा और महिलाएं: बदलती तस्वीर, कड़वी हकीकत

स्वतंत्रता का वादा, सुरक्षा का इम्तिहान

संवादिका • 04 October 2026 • रविवार • Sunday

लेखिका पिकी कुंडू, सामाजिक परामर्शदाता

मुख्य विद्व./सुविचारक SAFETY POINTS

- सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में विष्का vs राजस्थान के मामले में सुरक्षा के प्राथमिक अधिकार को स्थापित किया।
- महामा 2017 में निरभया के मामले में सुरक्षा के प्राथमिक अधिकार को स्थापित किया।
- BNS 73-77 में छेड़छाड़, पीछा करना, धूमना, सार्वजनिक स्थान पर अश्लील हरकत पर 3 से 7 साल तक की सजा। सड़क पर हुआ उत्पीड़न अब सिर्फ छेड़छाड़ नहीं, गंभीर अपराध।
- AIS-140 और GPS का अनिवार्य होना और VLTLD ट्रैकिंग का अनिवार्य होना।
- एम्प्लॉय 2013 में सुरक्षा के प्राथमिक अधिकार को स्थापित किया।

संपादकीय विवरण

- संपादिका: पिकी कुंडू, सामाजिक परामर्शदाता
- लेखिका: पिकी कुंडू, सामाजिक परामर्शदाता
- संपादिका: पिकी कुंडू, सामाजिक परामर्शदाता
- लेखिका: पिकी कुंडू, सामाजिक परामर्शदाता

संपादकीय विवरण

- संपादिका: पिकी कुंडू, सामाजिक परामर्शदाता
- लेखिका: पिकी कुंडू, सामाजिक परामर्शदाता
- संपादिका: पिकी कुंडू, सामाजिक परामर्शदाता
- लेखिका: पिकी कुंडू, सामाजिक परामर्शदाता

परिवहन विशेष
Transport Special National Newspaper

संवादिका • 04 October 2026 • रविवार • Sunday

लेखिका पिकी कुंडू, सामाजिक परामर्शदाता

वाहनों में महिला सुरक्षा - हक भी, अधिकार भी और कानून भी जानिए आपके अधिकार, कानून और हेल्पलाइन

लेखिका पिकी कुंडू, सामाजिक परामर्शदाता

1. आपका हक

- अनुच्छेद 14, 15, 21
- सुरक्षित यात्रा मौलिक अधिकार

2. आपका अधिकार

- सर्वजनिक मोटर वाहन
- शेरी बस का स्टॉप

3. कानून

- BNS 73-77 (छेड़छाड़, पीछा करना, धूमना)
- POSH Act 2013, निरभया के मामले में

4. क्या करें

- 112 / 1090 / 181 पर कॉल
- AIS-140 पैक बटन दबाएं
- VLTLD ट्रैकिंग सुनिश्चित करें

5. नियोजकों की जिम्मेदारी

- राति पाली में सुरक्षित दस्तावेज अनिवार्य

महिला हेल्पलाइन - 24x7 सहायता

112 1090 181

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति

संपादिका: पिकी कुंडू, सामाजिक परामर्शदाता

लेखिका: पिकी कुंडू, सामाजिक परामर्शदाता

संपादिका: पिकी कुंडू, सामाजिक परामर्शदाता

लेखिका: पिकी कुंडू, सामाजिक परामर्शदाता

फुटपाथ पर स्ट्रीट लाइट नहीं होना, अनुच्छेद 21 का उल्लंघन मानकर जनहित याचिका योग्य।

2. फुटपाथ - सम्मान: सुप्रीम कोर्ट का आदेश - फुटपाथ पैदल यात्रियों का है, अतिक्रमण नहीं। महिलाओं को सड़क पर चलने को मजबूर करना लापरवाही है।

3. सार्वजनिक परिवहन की गुणवत्ता: केवल बसें नहीं, साफ बस स्टॉप, महिला कंडक्टर की नियुक्ति, समय-सारिणी का पालन।

4. 112 इंडिया ऐप: सभी महिलाओं के फोन में अनिवार्य - एक बटन से पुलिस।

5. ग्रामीण कनेक्टिविटी: PMGSY-III में अब 'स्कूल-हॉस्पिटल-बाजार' को जोड़ने वाली सड़कों को प्राथमिकता, ताकि ग्रामीण छात्राओं का ड्राइव-आउट रुके।

6. नियोजकों की जिम्मेदारी: Shops and Establishments Act में - रात्रि पाली में काम करने वाली महिलाओं को सुरक्षित ट्रांसपोर्ट देना कंपनी की कानूनी जिम्मेदारी (दिल्ली हाईकोर्ट आदेश 2019)।

7. सोच में बदलाव: स्कूल पाठ्यक्रम में सड़क सुरक्षा और जेंडर सम्मान - NCERT ने 2022 में शामिल किया।

निष्कर्ष - संपादकीय टिप्पणी: सड़क एक सार्वजनिक वादा है। यह वादा तभी पूरा होगा जब हम सड़क को केवल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि अनुच्छेद 15(3) के तहत महिलाओं के लिए सुरक्षित पहुँच का संवैधानिक दायित्व मानेंगे।

तकनीक (GPS, CCTV, 112) मदद करेगी, पर असली समाधान - अच्छी डिजाइन, जिम्मेदार पुलिसिंग और सम्मान की संस्कृति में है। वास्तव में विकसित भारत वह नहीं जहाँ महिलाओं को यात्रा की अनुमति है, बल्कि वह जहाँ वे आत्मविश्वास से यात्रा कर सकें।

जनहित में प्रकाशन हेतु नोट: यह रिपोर्ट जन-जागरूकता हेतु है।

दिल्ली परिवहन विभाग और दिल्ली यातायात पुलिस जिस कार्य को करने में नाकाम है वह भी उच्च न्यायालय के आदेश के बाद उसी कार्य को अन्य राज्यों में पुलिस चौकी वाले करने में कामयाब आखिर क्यों और कैसे ?

उत्तर प्रदेश पुलिस
लखनऊ कमिश्नरेट

मुंशी पुलिया पर यातायात व्यवस्था सख्त - ई-रिक्शा चालकों के लिए निर्देश

स्थान: मुंशी पुलिया, लखनऊ | प्रभावी: अक्टूबर 2026 से

ई-रिक्शा चालकों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश

- महिलाओं और राहगीरों को जबरदस्ती न बैठाएं**
 - सामानपूर्वक व्यवहार करें, जबरदस्ती सवारी बिठाना दंडनीय अपराध है
- चौराहे से 100 मीटर दूर ई-रिक्शा खड़ा करें**
 - चौराहे/जंक्शन के 100 मीटर के दायरे में पार्किंग पूरी तरह प्रतिबंधित
- माइक अनाउंसमेंट से जागरूकता**
 - नियमित माइक अनाउंसमेंट द्वारा यात्रियों को नियमों की जानकारी दें
- यातायात नियमों का पालन करें**
 - हेलमेट, सीट बेल्ट, निर्धारित गति एवं सिग्नल का पालन अनिवार्य

जारीकर्ता: लखनऊ कमिश्नरेट, मुंशी पुलिया ट्रैफिक पुलिस
• DCP पूर्वी: दीक्षा शर्मा • ACP: अतुल पांडे • थाना: गाजीपुर एवं इंदिरा नगर

तिथि: अक्टूबर 2026

जनसूचना: परिवहन विशेष समाचार पत्र | सड़क सुरक्षा - हमारा दायित्व | हेल्पलाइन: 112 / 1073

मुंशी पुलिया पर ई-रिक्शा

अराजकता पर पुलिस का शिकंजा - महिलाओं को जबरन बैठाने पर रोक, चौराहे से 100 मीटर दूर लगेंगे रिक्शा

लखनऊ कमिश्नर के निर्देश पर DCP पूर्वी दीक्षा शर्मा के आदेश से थाना गाजीपुर और इंदिरा नगर का संयुक्त अभियान, माइक से किया गया जागरूक

रिपोर्ट विशेष संवाददाता परिवहन विशेष लखनऊ, मुंशी पुलिया

राजधानी के सबसे व्यस्त चौराहों में से एक मुंशी पुलिया चौराहे पर यातायात व्यवस्था और महिला सुरक्षा को लेकर लखनऊ पुलिस ने शनिवार शाम को बड़ा अभियान चलाया। थाना गाजीपुर और थाना इंदिरा नगर पुलिस की संयुक्त टीम ने ई-रिक्शा चालकों को सख्त हिदायत दी।

मुख्य तथ्य और कार्रवाई:

1. महिलाओं को जबरन बैठाने पर सख्त रोक: पुलिस को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि कुछ ई-रिक्शा चालक महिलाओं और राहगीरों का हाथ पकड़कर या धेरकर जबरदस्ती बैठाने का प्रयास करते हैं। पुलिस ने स्पष्ट किया कि बिना सहमति के किसी भी यात्री को बैठाना दंडनीय अपराध है और इससे महिला सुरक्षा पर सवाल खड़ा होता है।

2. चौराहे से 100 मीटर दूरी का नियम लागू: यातायात जाम की मुख्य वजह चौराहे पर ही ई-रिक्शा खड़े करना है। अब सभी ई-रिक्शा चालकों को निर्देश दिया गया है कि वे मुंशी पुलिया चौराहे से करीब 100 मीटर की दूरी पर ही अपने वाहन खड़े करें। चौराहे की 100 मीटर परिधि में पार्किंग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।

3. उच्च अधिकारियों के निर्देशन में अभियान: यह अभियान लखनऊ पुलिस कमिश्नर के दिशा-निर्देशन में, DCP पूर्वी दीक्षा शर्मा के आदेश और ACP गाजीपुर अतुल कुमार पांडे की देखरेख में चलाया गया। मौके पर थाना गाजीपुर प्रभारी राजेश कुमार मोर्य अपनी पूरी टीम के साथ और थाना इंदिरा नगर इंसपेक्टर अजय नारायण सिंह की टीम मौजूद रही। प्रभावी निरीक्षण खुद चौराहे पर पैदल घूमकर व्यवस्था का जायजा लेते दिखे।

4. माइक अनाउंसमेंट और पैदल गश्त: पुलिस टीम ने माइक से अनाउंसमेंट कर ई-रिक्शा चालकों और राहगीरों को जागरूक किया। शाम के समय पुलिस की पैदल गश्त से बाजार और चौराहे से गुजर रहे लोगों में सुरक्षा का भरोसा देखा गया।

पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि यातायात नियमों का पालन करें और यदि कोई ई-रिक्शा चालक जबरदस्ती करता है या जाम लगाता है तो तुरंत 112 या संबंधित थाने को सूचना दें।

निष्कर्ष: राजधानी दिल्ली को प्रदूषित हवा, सड़कों पर जाम और हादसे, पटरियों, सड़कों और चौराहों पर जाम लगवाने वाला कैसे कर सकता है वो कार्य जो जनहित में हो पर सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के हित में नहीं, यही सच है जो राजधानी को प्रदूषण मुक्त, जाम मुक्त, हादसे मुक्त और अवैध कब्जा मुक्त नहीं होने देता। यही वो कारण भी है जो सरकारी राजस्व में भी अरबों - खरबों रुपये बिना किसी कारण पैदा करवाता है।

यानी आम के आम और गुठलियों के भी दाम भारत सरकार और राज्य सरकारों को बिना गिनती का राजस्व और सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की भी पो बारह

टैपल आफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर अलाइड ट्रस्ट पंजीकृत

https://tolwa.com/about.html | tolwaindia@gmail.com, tolwadelhi@gmail.com



पिकी कुंडू

आज का साइबर सुरक्षा विचार: Chrome में बायोमेट्रिक ऑटोफिल: पासवर्ड सुरक्षा और गोपनीयता की नई ढाल



है।

- फ्रिंशिंग जोखिम कम करता है: बायोमेट्रिक के साथ ऑटोफिल केवल असली साइट्स पर क्रेडेंशियल्स रिलीज करता है।

- शेयर किए गए वातावरण में सुरक्षा: ऑफिस, कैफे या परिवार में साझा डिवाइस पर अनधिकृत लॉगिन रोकता है।

2. गोपनीयता सुरक्षा

- क्रेडेंशियल्स डिवाइस मालिक से जुड़े रहते हैं: पासवर्ड तभी ऑटोफिल होगा जब रजिस्टर्ड फिंगरप्रिंट/फेस/PIN मैच करे।

- सेंटिंग्स में पासवर्ड एक्सपोज नहीं होगे: कोई भी Chrome सेंटिंग्स ब्राउज करके पासवर्ड नहीं देख सकता।

- सर्वर साइड जोखिम कम: पासकी और बायोमेट्रिक के साथ केवल पब्लिक की सर्वर पर स्टोर होती है।

3. उपयोगकर्ता अनुभव सुधार

- सुविधा + सुरक्षा: ऑटोफिल की स्पीड बनी रहती है, पर सुरक्षा की परत जुड़ जाती है।

- डिवाइसों पर सहजता: पासकी और बायोमेट्रिक Android, Desktop Chrome और अन्य प्लेटफॉर्म पर स्मूद ट्रांजिशन देते हैं।

जोखिम और समझौते

- थोड़ी देर: हर बार ऑथेंटिकेशन करना होगा।

- बायोमेट्रिक विश्वसनीयता: गीले/धूल पर हालात में सेंसर फेल हो सकते हैं, PIN बैकअप जरूरी है।

- डिवाइस निर्भरता: बायोमेट्रिक बंद या खराब होने पर सुरक्षा कमजोर हो सकती है।

व्यावहारिक सलाह

- Chrome सेंटिंग्स में बायोमेट्रिक ऑटोफिल सक्षम करें (Google Password Manager → Autofill → Require screen lock/biometric)।

- "Auto sign in" बंद करें ताकि बिना पुष्टि के लॉगिन न हो।

- मजबूत PIN रखें जो बायोमेट्रिक का बैकअप बने।

- पासकी का उपयोग करें ताकि फ्रिंशिंग से अधिकतम सुरक्षा मिले।

Chrome सेंटिंग्स में बायोमेट्रिक ऑटोफिल सक्षम करें, यदि पहले से नहीं किया है। बायोमेट्रिक चेक Chrome के ऑटोफिल में एक बड़ा सुरक्षा अपग्रेड है: यह आकस्मिक दुरुपयोग रोकता है, धोखाधड़ी को ब्लॉक करता है और आपके पासवर्ड को निजी रखता है—even अगर आपका फोन अनलॉक या साझा किया गया हो।

Google Chrome (Android) अब पासवर्ड ऑटोफिल से पहले बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन (फिंगरप्रिंट, फेस अनलॉक या PIN) को मांग करेगा। यह कदम धोखाधड़ी के जोखिम को कम करता है और सुनिश्चित करता है कि केवल असली डिवाइस मालिक ही क्रेडेंशियल्स तक पहुँच पाए, साथ ही गोपनीयता को भी मजबूत करता है।

Chrome (Android) में Biometric Autofill के मुख्य लाभ

1. धोखाधड़ी रोकथाम

- "Walk up autofill" हमलों को रोकता है: बिना बायोमेट्रिक के, कोई भी आपके अनलॉक फोन से लॉगिन पेज खोलकर क्रेडेंशियल्स ऑटोफिल कर सकता है। बायोमेट्रिक इसे ब्लॉक करता

परिवहन विशेष समाचार पत्र से जुड़े सभी पाठकों और सहयोगियों के लिए विशेष सूचना

परिवहन विशेष समाचार पत्र को जिस तरह आप लोगों के सहयोग लगातार पिछले 3 वर्षों से प्राप्त हुआ और दिन प्रतिदिन आपकी आवाज को आगे पहुँचाने में आपका सहयोगी बना उसको देखते हुए परिवहन विशेष समाचार पत्र के प्रबंधक मंडल और ट्रांसपोर्ट विशेष न्यूज लिमिटेड कंपनी द्वारा जनहित, जनकल्याण जनसूचना और जानकारी को और तेजी से भारत सरकार और राज्य सरकारों के साथ सभी राजनीतिक संगठनों को सबसे पहले पहुँचाने के उद्देश्य से अक्टूबर माह से जनता की आवाज का अपना चैनल "परिवहन विशेष न्यूज दूरदर्शन" शुरू करने का निर्णय लिया है।

जल्द आपके बीच में....



परिवहन विशेष न्यूज दूरदर्शन

बड़ी खुशखबरी! अब आपकी आवाज गुंजेगी पूरी दुनिया में परिवहन विशेष समाचार पत्र के सफल 3 वर्षों के बाद अब नई क्रांति



संजय बाठला

मुख्य संपादक

आशा करते हैं की हम अपने चैनल के माध्यम से आपको 1. प्रतिदिन की देश विदेश की जानकारी 2. आपके वह आपके बच्चों के कैरियर, 3. आपके बच्चों के भविष्य से संबंधित ज्ञानवर्धक आवश्यक जानकारी, 4. आपकी सेहत से जुड़ी सभी उपयोगी जानकारी, 5. शारीरिक बीमारियों से बचने के तरीके 6. धार्मिक एवं आध्यात्मिक ज्ञान विश्व के सभी क्षेत्रों के ज्ञानदाताओं के माध्यम से प्रदान करने का प्रयास करेंगे। हम अपने चैनल द्वारा प्रतिदिन एक घंटे के कार्यक्रम "जनता की पुकार" में आपकी आवाज को विश्व के सामने प्रस्तुत कर सरकार और सरकारी विभागों के साथ माननीय न्यायालयों से उसके उचित हल और उसके प्रति पालिसी लागू करवाने में मध्यांतर का माध्यम बनेंगे। आप सभी से अनुरोध आप के अपने शुरू होने वाले चैनल के माध्यम से अपनी शिकायतें, परेशानियाँ और अनुभव अन्य सभी से साझा करने के लिए तैयार एवं तत्पर रहे। आशा करते हैं जैसे आपने आज के इस दौर में "परिवहन विशेष समाचार पत्रों" को इतना आगे ले कर जाने में सहयोग दिया उसी प्रकार हमारे द्वारा आपकी आवाज बनने के लिए शुरू किए जा रहे "परिवहन विशेष न्यूज दूरदर्शन" को विश्व का सबसे बड़ा चैनल बनवाएंगे।

आंगन मिलन सेवा के जरिए महिलाओं को पोषण और संतुलित आहार का संदेश

गांव दूजाना में घर के पास मिला प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का बेहतर माहौल, विद्यार्थियों का बच रहा समय और धन

गांव ग्वालिसन स्थित आंगनबाड़ी केंद्र पर
बुध अध्यक्ष अजय शर्मा और गांव
मातनहेल में आयोजित कार्यक्रम में बीजेपी
पूर्व मंडल अध्यक्ष जगदीश ने बतौर मुख्य
अतिथि लिया भाग
खंड साल्हावास और मातनहेल आंगनवाड़ी
केंद्रों पर तीन दिवसीय कार्यक्रम के
समापन अवसर पर हेल्पर, वर्कर और
आशा कार्यकर्ता का हुआ सम्मान
कार्यक्रमों में महिलाओं, किशोरियों और
बच्चों ने बढ़-चढ़कर लिया भाग
परिवहन विशेष न्यून

झज्जर, 03 अक्टूबर। जिलाभार में डीसी वर्षा खांगवाल के मार्गदर्शन में 17 अक्टूबर तक 'सेवा संयुक्त अभियान' के तहत अनेक गतिविधियां जारी हैं। इसी कड़ी में 'आंगन मिलन सेवा' मॉड्यूल के तहत महिला एवं बाल विकास विभाग के तत्वावधान में खंड मान-नहेल और साल्तावास के आंगनवाड़ी केंद्रों पर आयोजित तीन दिवसीय कार्यक्रमों का शनिवार को समापन हुआ।

गांव ग्वालिसनस्थित आगनबाड़ी
केंद्र पर बतौर मुख्य अतिथि बूथ अध्यक्ष
अजय शर्मा ने भाग लिया, जबकि
अध्यक्षता सरपंच प्रीति ने की। वहीं गांव

मातनहेल में आयोजित कार्यक्रम में बीजेपी
पूर्व मंडल अध्यक्ष जगदीश और
सरपंच विनय लता ने भाग लेकर
महिलाओं से सरकार की नीतियों का लाभ
उठाने का आह्वान किया।
मुख्य मेहमानों ने सभी वर्कर, हेल्पर,
आशा वर्कर को सम्मानित किया।
कार्यक्रम के अंतिम दिनांक आंगनवाड़ी केंद्रों
पर पोषण, स्वास्थ्य और स्वस्थ जीवनशैली से
जुड़ी विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया
गया। महिलाओं, किशोरियों और बच्चों ने
उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए स्वस्थ जीवनशैली
अपनाने का संदेश दिया।

पोषण और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पर रहा जोश

जिला कार्यक्रम अधिकारी नेहा दहिया ने बताया कि 'आंगन मिलन सेवा' माँझूल के माध्यम से आंगनवाड़ी केंद्रों को केवल पोषण सेवाओं तक सीमित न रखते हुए पोषण, स्वास्थ्य, योग और स्वस्थ जीवनशैली के प्रति जागरूकता के केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिलाओं और बच्चों को स्वस्थ खान-पान तथा बेहतर जीवनशैली के लिए प्रेरित करना है। साथ ही महिलाओं को महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए



भी जागरूक किया गया।

बाल विकास में संतुलित पोषण की भूमिका समझाई

मातनहेल में सुपरवाइजर सुमन रानी तथा गवालियनन में सुपरवाइजर रश्मि रानी क्षेत्र के आंगनवाड़ी केंद्रों में सुपरवाइजर शिमरा रानी के नेतृत्व में पोषण संबंधी गतिविधियाँ आयोजित की गई। विभागीय टीमों ने लाभार्थियों को योजनाओं की जानकारी देने के साथ-साथ बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य एवं विकास में संतुलित पोषण की भूमिका समझाई।

महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए योजनाओं की जानकारी

सुपरवाइजर रश्मि और सुमन ने कार्यक्रम

के दौरान प्रथममंत्री मातृ वंदना योजना, मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना, मुख्यमंत्री मातृत्व एवं शिशु कल्याण योजना सहित आंगनवाड़ी आधारित स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी योजनाओं को जानकारी भी दी। महिला व किशोरी लाभार्थियों को पात्रता के अनुसार योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया गया।

‘आंगन मिलन सेवा’ के तीन दिवसीय आयोजन ने आंगनवाड़ी केंद्रों को पोषण, संवाद और जन जागरूकता के जीवंत मंच के रूप में सामने रखा। जागरूकता गतिविधियों के माध्यम से महिलाओं और बच्चों में स्वस्थ खान-पान तथा बेहतर जीवनशैली को लेकर

जागरूकता बढ़ाने का संदेश दिया गया।
केंद्रों में पेंटिंग और रंगोली
प्रतिस्पर्धाओं का भी हुआ आयोजन
 साह्लावास और माननेहल, गवालिशन,
 कानूनी सहित सभी आगवानी के केंद्रों पर
 पेंटिंग, रंगोली, स्वस्थ बालक-बालिका स्पर्धा
 सहित विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से बच्चों
 और महिलाओं को पोषण के महत्व से जोड़ा
 गया। आगवानी कार्यक्रमों और एवं विभागीय
 टीमें ने लाभार्थियों से संवाद करते हुए बच्चों
 की उचित वृद्धि एवं विकास, संतुलित आहार,
 स्वच्छता, स्वास्थ्यवर्धक आदतों और
 सामुदायिक स्वास्थ्य से संबंधित महत्वपूर्ण
 जानकारी दी।

तीन दिवसीय कार्यक्रम के अंतिम दिन
15 हजार 352 लाभार्थियों ने की
सहभागिता
तीन दिवसीय कार्यक्रम के दौरान खंड
साल्हावास के 111 आंगनवाड़ी केंद्रों तथा खंड
मातनहेल के 148 आंगनवाड़ी केंद्रों पर
आयोजित गतिविधियों में बड़ी संख्या में
लाभार्थियों ने भाग लिया। अंतिम दिन खंड
साल्हावास से 6629 तथा मातनहेल से
8,723, कुल 15,352 लाभार्थियों ने
सहभागिता की। इस अवसर पर अनिता देवी,
राजवंती, कृष्णा, राजपति के अलावा अन्य
महिलाएं उपस्थित रही।

**सेवा संकल्प अभियान: नमो
सेवा अनकही कहानियां के
तहत झज्जर जिला में 4 व 5
अक्टूबर को होंगे नुक्कड़ नाटक**

प्रचार टीम नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जनकल्याणकारी योजनाओं की देगी जानकारी

परिवहन विशेष न्यूज

झज्जर, 3 अक्टूबर

सेवा संकेतप अभियान के तहत डीसी र्षां खांगवाल के मार्गदर्शन में 'नमो सेवा अनकही कहानियाँ' माँडयूल के तहत झज्जर जिला में आंगमी के व 5 अक्टूबर को विभिन्न गांवों, शिक्षण संस्थानों और महाविद्यालयों में नुकड़ नाटक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों के माध्यम से प्रचार टीमों द्वारा आमजन को सरकारी जनकल्याणकारी योजनाओं एवं जन्हित से जुड़ी सेवाओं की जानकारी दी जाएगी।

4-5 अक्टूबर को इन स्थानों पर होंगे कार्यक्रम
रविवार, 4 अक्टूबर को गांव डाबोदा खुर्द, वुपनिया, मांडोठी, नूना माजरा, छुडानी, जहांगीरपुर, सिलानी केशो, खुड्डन, कुलाना, दुजाना, डीघल तथा दूबलधन विधायन में नुकड़ नाटक

आयोजित किए जाएंगे। वहीं सोमवार, 5 अक्टूबर को राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बहादुरगढ़, राजकीय महिला महाविद्यालय बहादुरगढ़, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय लडरावन, राजकीय आईटीआई आसौदा डोडरान, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय माछरौली, नेहरू पूंजी कॉलेज झज्जर, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बेरी, राजकीय कॉलेज दुजाना तथा गांव गुभाना, रोहट, खेड़ी खुम्मार व बिरथाना में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

प्रवक्ता ने बताया कि नुक्कड़ नाटक के माध्यम से प्रचार टीम द्वारा आमजन को सरल एवं रोचक तरीके से विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं, सरकारी सेवाओं तथा जनहितकारी पहलों की जानकारी दी जाएगी। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों तक योजनाओं की जानकारी पहुंचाकर उन्हें सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए जागरूक करना है।

युवाओं की नवाचारी सोच से बनेगा विकसित भारत : दिनेश शेखावत

जिला संयोजक दिनेश शेखावत ने युवाओं को नवाचार, उद्यमिता और जनसेवा के लिए किया प्रेरित बालौर रोड स्थित राजकीय महाविद्यालय में 'सेवा फर्स्ट इनोवेशन चैलेंज' कार्यक्रम आयोजित



विकासित भारत का निर्माण केवल सरकारी योजनाओं से नहीं, बल्कि युवाओं की नवाचारी सोच और जनसेवा की भावना से होगा।

उन्होंने कहा कि युवा केवल नौकरी तलाशने वाले नहीं, बल्कि रोजगार सृजित करने वाले और समाज की समस्याओं का समाधान देने वाले बनें।

शेखावत ने कहा कि युवाओं को समस्याओं पर चर्चा करने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उनके व्यावहारिक

समाधान प्रस्तुत करने चाहिए।
उन्होंने बताया कि सेवा फर्स्ट इनोवेशन
‘चेलेंजर्स’ कार्यक्रम युवाओं को समाज और
शासन व्यवस्था से जुड़ी वास्तविक
समस्याओं के समाधान तलाशने का मंच
प्रदान करता है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र
मोदी के नेतृत्व में स्टार्टअप इंडिया, मेक इन
इंडिया, डिजिटल इंडिया और स्किल इंडिया
जैसी पहलों से युवाओं के लिए नए अवसर
पैदा हुए हैं।

उन्होंने विद्यार्थियों से अपने आसपास की समस्याओं को पहचान कर उनके समाधान जिला नवाचार को का आह्वान किया ।

निला उद्योग केंद्र के उद्योग विस्तार अधिकारी मंजीत देहिया ने विद्यार्थियों को स्टार्टअप, स्वरोजगार और उद्यमिता विकास की जानकारी दी ।

कार्यक्रम में विद्यार्थियों को नशामुक्त और जागरूक भारत के निर्माण का संकल्प दिलालाया गया ।

कार्यक्रम में बहारादुगढ़ विधानसभा क्षेत्र के योगेज एवं नगर परिषद चेयरमैन सरोज देवी, पाले उपमंडल, राम अहलावत, पंकज गुप्त, सुदेश रंगा के अलावा डॉ. अमित खन्ना, नोडल अधिकारी प्रोफेसर जोगेंद्र सिंह, प्रोफेसर मनोज कुमार, प्रोफेसर राजीव मसीवाल, प्रोफेसर राजीव देहिया, प्रोफेसर हरिण कृष्ण और डॉ. मीनाक्षी और डॉ. सीमा सिंह प्राध्यापकगण उपस्थित रहे ।

अवैध औद्योगिक गतिविधियों व प्लास्टिक/कचरा जलाने पर रोक के आदेश जारी : जिलाधीश

आवासीय व कृषि क्षेत्रों में बिना अनुमति औद्योगिक गतिविधियां संचालित करने वालों पर होगी कार्रवाई

जिलाधीश वर्षा खांगवाल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी किए आदेश

झज्जर/बहादुरगढ़, 03
अक्टूबर
 जिलाधीश वर्षा खांगवाल ने जिला
 में आवासीय एवं कृषि क्षेत्रों में संचालित
 अवैध औद्योगिक गतिविधियों तथा
 प्लास्टिक/कचरा जलाने की घटनाओं
 को रोक लगाने के लिए भारतीय
 नगरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा
 163 के तहत निषेधाज्ञा आदेश जारी
 किए हैं। जिलाधीश की ओर से जारी
 आदेशानुसार जिला के गांव परनाला,
 नैनजामपुर रोड, बामनोली, कोनांदा,
 खेरपुर, लडावगण, सिदीपुरा, लोवा

लोवा खुद क्षेत्रों में आवासीय व
मूमि पर प्लास्टिक/कचरा जलाने
कायते सामने आई है। इन
विधियों से प्रदूषण बढ़ने के साथ-
आमजन के स्वास्थ्य और जीवन
गवता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा
होने कहा कि जनहित को ध्यान में
हूए ऐसे सभी अवैध औद्योगिक
हस्तिकार राज्य प्रदूषण नियंत्रण
एचएसपीसीबी) की अनुमति के
बी कंक्शन का उपयोग कर
गिक गतिविधियां संचालित करने
में प्रतिबंध लगाया गया है।
तलाधोश ने बताया कि आदेश
ल प्रभाव से लागू हो गए हैं और 03
र 2026 तक प्रभावी रहेगे।
ओं की पालना सुनिश्चित करवाने
ए, एसईए विभाग, डीएमसी
र, एसईए यूएचबीवीएनएल झंझर,



पीपी इज़रत, बीडीपीओ बहादुरगढ़,
ग्रीष्म अधिकारी एचएसपीसीबी
दुर्गगढ़ तथा कार्यकारी अधिकारी
पर परिषद बहादुरगढ़ को जिम्मेदारी
मि गई है।
उन्होंने स्पष्ट किया आदेशों की
महलना करने वाले व्यक्तियों के
अनुसार भारतीय न्याय संहिता की धारा
3 के तहत नियमानुसार कार्यवाई की
गयी। उन्होंने आमजन से अपील की
कि वे पर्यावरण संरक्षण एवं स्वास्थ्य
के दृष्टिगत इन आदेशों की
अंतिम से पालन करें।

सेवा संकल्प अभियान- ग्रामीणों के लिए लाभकारी साबित हो रहे सेवा सेतु कैंप

सरकार की योजनाओं के लाभार्थी बनने सेवा सेतु कैम्प में बेरी पहुंचे ग्रामीण



सरकार की योजनाओं के लाभार्थी बनने सेवा सेतु कैम्प में बेरी पहुँचे ग्रामीण बेरी स्थित ब्लाक कार्यालय में मुख्य अतिथि पंचायत समिति चैयरमैन अंजू रानी ने सेवा सेतु कैम्प का किया अवलोकन

डीसी वर्षा खांगवाल के मार्गदर्शन तथा एसडीएम रेणुका नांदल के निर्देश अनुसार विभिन्न विभागों ने स्टॉल लगाकर दी योजनाओं की जानकारी

परिवहन विशेष न्यूज

बेरी (झज्जर), 03 अक्टूबर
सेवा संकल्प अभियान के तहत नागरिकों को सरकारी सेवाओं एवं सहाज रूप से उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से बेरी ब्लाक कार्यालय परिसर में शनिवार को सेवा सेतु कैम्प का आयोजन हुआ।

मुख्य अतिथि के रूप में पंचायत समिति चैयरमैन अंजू रानी

ने सेवा सेतु कैम्प का शुभारंभ किया।

कैप में पहुँचने पर बीडीपीओ धर्मपाल ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया। कैप में बड़ी संख्या में क्षेत्रवासियों ने पहुँचकर विभिन्न विभागों की योजनाओं एवं सेवाओं की जानकारी प्राप्त की और उपलब्ध सुविधाओं का लाभ उठाया। गौरतलब है कि डीसी वर्षा खांगवाल के मार्गदर्शन और एसडीएम रेणुका नांदल के निर्देश अनुसार वही क्षेत्र में सेवा संकल्प अभियान के तहत सेवा सेतु कैप लगाकर लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है।

नागरिकों को सरकार द्वारा चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं, सेवाओं और कार्यक्रमों की दी जानकारी

मुख्य अतिथि

इस दौरान पंचायत समिति चैयरमेन अंजु रानी विशेष रूप से बताया कि कैप में विभिन्न विभागों की ओर से स्टॉल लगाए गए हैं, जहाँ विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा कि नागरिकों को सरकार द्वारा चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं, सेवाओं और कार्यक्रमों की



जानकारी दी जा रही है। नागरिकों को योजनाओं के लिए निर्धारित पात्रता, आवेदन प्रक्रिया तथा मिलने वाले लाभों के बारे में भी विस्तार से बताया गया।

उन्होंने कहा कि सेवा संकल्प अभियान के तहत आयोजित किए जा रहे सेवा सेतु कैंप का उद्देश्य सरकारी योजनाओं और सेवाओं को आमजन के करीब पहुंचाना है, ताकि पात्र नागरिकों को योजनाओं की जानकारी के लिए अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़े और उन्हें एक ही स्थान पर आवश्यक जानकारी एवं मार्गदर्शन मिल सके।

मुख्य अतिथि अंजू रानी ने ग्रामीणों से आह्वान किया कि वे प्रशासन की ओर से शेड्यूल अनुसार सेवा सेतु कैंप में पहुंचकर विभिन्न विभागों की योजनाओं एवं सेवाओं की जानकारी प्राप्त करें और अपनी पात्रता के अनुसार सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाएं।

स्वास्थ्य संरक्षण, स्वस्थ जीवनशैली के लिए कैंप प्रेरित

सेवा सेतु कैंप में स्वास्थ्य एवं आयुष

विभाग की ओर से स्वास्थ्य जांच शिविर भी लगाया गया। यहां नागरिकों की स्वास्थ्य जांच कराने के साथ उन्हें स्वास्थ्य संरक्षण, स्वस्थ जीवनशैली तथा आयुष्य पद्धति से संबंधित आवश्यक जानकारी एवं परामर्श दिया गया। इससे कैप में आने वाले नागरिकों को सरकारी योजनाओं की जानकारी के साथ स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का भी लाभ मिला।

कैप में विभिन्न योजनाओं से संबंधित जानकारी लेने के लिए नागरिकों में उत्साह देखने को मिला। लोगों ने विभागीय स्टॉल पर पहुंचकर अपनी जरूरत के अनुसार जानकारी प्राप्त की तथा पात्रता के आधार पर योजनाओं का लाभ लेने के लिए आवश्यक प्रक्रिया को समझा। अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने आमजन को सरकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर एड्सपीओ सत्यनारा अहलावत, ब्लॉक कॉर्डिनेटर पूनम सैनी सहित अन्य स्टाफ सदस्य उपस्थित रहे।

फ्रील्ड मॉनिटरिंग और
वेबक रेस्पॉन्स टीमों को
रखें सक्रिय, जरूरत के
अनुसार ड्रोन से भी होगी
निगरानी
पराली खेत में मिलाने पर
केसानों को प्रति एकड़
1200 रुपये की प्रोत्साहन
राशि, पंचायतों व
जनप्रतिनिधियों को अभियान
से जोड़ने के निर्देश

डज्जर, 03 अक्टूबर।
जिला में पराली प्रबंधन को बढ़ावा देने, फसल अवशेष जलाने के बजाए घटनाओं पर प्रभावी होने तकनीक और वायु गुणवत्ता बनाए रखने को लेकर जिला प्रशासन द्वारा लगातार निगरानी एवं जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। डीसी वर्षा ऋतुगवाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन की वैज्ञानिक एवं वैल्पिक तकनीकों की जानकारी देते हुए पराली न जलाने के लिए निरंतर प्रेरित किया जाए।
डीसी ने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण उपायों की कड़ाई से पालना सुनिश्चित करने के साथ-साथ भील्ड में नियमित निगरानी की जाए। पराली जलाने की संभावित घटनाओं की तत्काल सूचना और प्रभावी कार्रवाई के लिए किंवदन्तियों से दूर सक्रिय रहें। उन्होंने कहा कि फसल अवशेष जलाने से पर्यावरण प्रदूषित होने के साथ मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी प्रभावित होती है, इसलिए किसानों को इसके दुष्प्रभावों और फसल अवशेष प्रबंधन के लाभों के बारे में



समझाना जरूरी है।
फील्ड विजिट के साथ
अधिकारी संभावित क्षेत्रों पर रखें
नजर
 डीसी ने संबंधित अधिकारियों को नियमित फील्ड विजिट करने तथा पराली जलाने की आशंका वाले क्षेत्रों में पहले से प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए। प्रदूषण फैलाने वाले संभावित स्रोतों की निगरानी के लिए आवश्यकता अनुसार ड्रोन का उपयोग करने और सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने को कहा। उन्होंने भुवन एण्ड और सी आरएम योजना के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी विशेष जोर दिया।
पराली प्रबंधन अपनाने पर प्रति
एकड़ 1200 रुपये प्रोत्साहन
 डीसी ने बताया कि कृषि विभाग की ओर से फसल अवशेष प्रबंधन के तहत पराली को खेत में मिश्राने पर किसानों को प्रति एकड़ 1200 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस योजना के साथ-साथ फसल अवशेष प्रबंधन की उपलब्ध मशीनरी एवं वैज्ञानिक तकनीकों की जानकारी भी

थक से अधिक किसानों तक पहुंचाई जाए।
उन्होंने कहा कि पंचायतों और स्थानीय जनमतनिधियों को भी पराली धन अभियान से सक्रिय रूप से जोड़ा जाए। किसानों के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखना और उन्हें पराली प्रबंधन पर्यावरणपरक और कृषि संबंधी लाभों से जोड़ने में जागरूक किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि पराली जलाने की प्रथाओं को रोकने में किसी भी स्तर पर परमावी बर्दाश्त नहीं की जाएगी तथा किसानों के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

किसानों के सहयोग से ही बनेगा चछ पर्यावरण

डीसी वर्षा खांगवाल ने कहा कि चछ पर्यावरण और बेहतर वायु प्रदूषण को रोकने के लिए, किसानों को प्रयासों के साथ किसानों को आमजन का सहयोग ही जरूरी है। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे जल अवशेषों को न जलाएं तथा जलबन्ध फसल अवशेष प्रबंधन तकनीकों और सरकारी योजनाओं का उपयोग कर पर्यावरण संरक्षण में भागी बनें।

भारत की अर्थव्यवस्था का दोहरा इम्तिहान - 75% वैश्विक व्यापार का लक्ष्य और वित्तीय बाजारों पर दबाव

लेखक: एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी, गोदिया (महाराष्ट्र) परिवहन विशेष समाचार पत्र

संभावनाओं और चुनौतियों का संगम: वैश्विक अर्थव्यवस्था के बदलते परिदृश्य में 3 अक्टूबर 2026 का दिन भारत के लिए दोहरी तस्वीर लेकर आया है। एक तरफ भारत मुक्त व्यापार समझौतों (FTA) के जरिए वैश्विक GDP के 75-80% हिस्से तक पहुंच बनाने, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सहकारिता से जोड़ने और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य पर आगे बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ शेयर बाजार में 25 साल बाद 8 सप्ताह की सबसे लंबी लगातार गिरावट, 26 लाख करोड़ से अधिक का बाजार पूंजीकरण स्वाहा होना और विदेशी मुद्रा भंडार में बड़ी कमी ने आर्थिक विमर्श को गंभीर बना दिया है।

1. मुख्य बिन्दु - वैश्विक व्यापार में महत्वाकांक्षा: भारत-न्यूजीलैंड FTA 20 अक्टूबर 2026 से प्रभावी होना तय है। सरकार का लक्ष्य केवल निर्यात नहीं, बल्कि MSME, कृषि प्रसंस्करण, वस्त्र, औषधि और इंजीनियरिंग उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय मानकों पर प्रतिस्पर्धी बनाना है। FTA बाजार खोलता है, पर असली लाभ तभी जब गुणवत्ता, कीमत और समयबद्ध आपूर्ति में हम वैश्विक स्तर पर खरे उतरें।

2. ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा - पशुपालन और सहकारिता: 3 अक्टूबर को सहकारिता मंत्रालय द्वारा पशुपालन आधारित धनत्रंज की अवधारणा समावेशी विकास का आधार है। दुग्ध सहकारी समिति, पशु चिकित्सा, चारा उत्पादन, नस्ल सुधार, शीत भंडारण और ग्रामीण ऋण की पूरी वैल्यू चेन से महिला सशक्तिकरण और रोजगार जुड़ा है। विकसित भारत का आकलन महानगरों से नहीं, गांव के पशुपालक की आय वृद्धि से होना चाहिए।

3. कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन - वित्तीय स्थिरता का संदेश: नई दिल्ली में 3-5 अक्टूबर तक 5वां कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन - विषय Resilience in an Age of Flux है। लगभग 30 देशों के अर्थशास्त्री शामिल। RBI गवर्नर का संदेश - वित्तीय दबाव अचानक उभरता है, दूर करने में वर्षों लगते हैं। पश्चिम एशिया संघर्ष, ऊर्जा कीमतें और बॉन्ड यील्ड में उछाल के बीच भारत में बॉन्ड यील्ड की सीमित वृद्धि हमारे प्रबंधन की मजबूती दर्शाती है।

4. तथ्य - विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट: RBI आंकड़ों के अनुसार 25 सितंबर 2026 को समाप्त सप्ताह में भंडार \$18.34 अरब घटकर \$747.56 अरब रह गया। 4 सितंबर के रिकॉर्ड \$785.71 अरब से 3 हफ्ते में कुल \$38.15 अरब की कमी। इसमें विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति में \$15.57 अरब और स्वर्ण भंडार में \$2.59 अरब की कमी शामिल। कारण - रुपये को संभालने के लिए संभावित हस्तक्षेप और डॉलर के मुकाबले यूरो/येन का मूल्योत्कन बदलाव। यह संकेत नहीं, पर निगरानी का विषय है।

5. तथ्य - शेयर बाजार का भूचाल: सेंसेक्स-निफ्टी लगातार 8 सप्ताह नीचे - 25 साल का सबसे लंबा गिरावट का दौर। 8 हफ्ते में निवेशकों के 26 लाख करोड़ से ज्यादा डूबे। 3 दिन में FII ने ₹29,613 करोड़ की शुद्ध बिकवाली की (2 अक्टूबर रिपोर्ट)। कारण - अमेरिकी 10-वर्षीय बॉन्ड यील्ड में तेजी, कच्चा तेल \$100/बैरल के ऊपर, रुपया कमजोर और भू-राजनीतिक तनाव।

6. ब्याज दरें पर नजर - RBI बैठक 5-7 अक्टूबर: MPC की बैठक 5-7 अक्टूबर को, निर्णय 7 अक्टूबर को संभावित। रॉयटर्स सर्वे 28 सितंबर - 60% अर्थशास्त्री 25 bps वृद्धि की उम्मीद में। Bank of America रिपोर्ट के अनुसार RBI अक्टूबर में 25 bps और 2027 पहली छमाही तक कुल 100 bps (1%) बढ़ोतरी कर रेपो रेट 6.25% तक ले जा सकता है। यह अनुमान है, घोषित निर्णय नहीं। अस्सर - होम, ऑटो लोन महंगा, पर महंगाई पर लगातार निष्कर्ष - संतुलन ही कुंजी: 5 अक्टूबर को बाजार की दिशा वैश्विक संकेत, कच्चा तेल, डॉलर-रुपया और FII प्लो से तय होगी। भारत के सामने दोहरी चुनौती है - बाहरी विस्तार (75% व्यापार लक्ष्य) और आंतरिक स्थिरता (बाजार, मुद्रा, महंगाई)। नीति निर्माताओं को व्यापार कूटनीति, ग्रामीण लचीलापन और वित्तीय सतर्कता के त्रिकोण पर एक साथ काम करना होगा।

बॉक्स - एक नजर में आंकड़े: - FTA लक्ष्य: 75-80% वैश्विक अर्थव्यवस्था तक पहुंच - शेयर बाजार: 8 हफ्ते लगातार गिरावट, 25 साल बाद रिकॉर्ड - माफेट कैप लॉस: ₹26 लाख करोड़ - फॉरेक्स: -\$18.34 अरब (एक हफ्ते में), कुल \$747.56 अरब - FII निकासी: 3 दिन में ₹29,613 करोड़ - RBI अनुमान: रेपो रेट 6.25% तक जा सकता है

भारत की अर्थव्यवस्था का दोहरा इम्तिहान

INDIA'S ECONOMY FACES DUAL TEST

SPECIAL ECONOMIC REPORT • 19 OCTOBER 2026 • EDITION

Key Developments as India Navigates External Pressures & Domestic Headwinds

1 75% वैश्विक व्यापार तक पहुंच का लक्ष्य

Target: 75% Access to Global Trade

India-NZ FTA • 20 Oct 2026

Comprehensive Free Trade Agreement signed, aims to expand exports to 75% of global markets by 2030

2 शेयर बाजार में 8 सप्ताह की ऐतिहासिक गिरावट

Stock Market Records 8-Week Historic Decline

25 साल बाद सबसे लंबा दौर - 26 लाख करोड़ डूबे

Longest slide in 25 years • ₹26 Lakh Cr wiped out

NIFTY 50: -12.4%

3 विदेशी मुद्रा भंडार में 18.34 अरब डॉलर की कमी

Forex Reserves Decline by \$18.34 Billion

अब कुल: 747.56 अरब डॉलर

Now at: \$747.56 Billion

Decline attributed to RBI intervention to stabilize Rupee

4 RBI मौद्रिक नीति बैठक 5-7 अक्टूबर 2026

RBI Monetary Policy Meeting: 5-7 Oct 2026

संभावित 25 bps वृद्धि - रेपो रेट 6.25% तक

Likely 25 bps hike • Repo rate to reach 6.25%

Inflation control priority amid rupee pressure and global rate scenario

5 विकसित भारत 2047 • ग्रामीण अर्थव्यवस्था पशुपालन सहकारिता

Viksit Bharat 2047 • Rural Economy & Cooperative Animal Husbandry

पशुपालन Animal Husbandry सहकारिता Farmer Cooperatives ग्रामीण विकास Rural Growth Target

Focus on boosting rural income, dairy & livestock sector, cooperative model expansion to strengthen rural economy by 2047 vision

दोहरा इम्तिहान: बाहरी दबाव + घरेलू चुनौती

Dual Test: External Trade & Financial Pressures + Domestic Market Volatility

Analysts say policy focus on stability, trade expansion, and rural resilience key to growth

SOURCE: RBI • NSE • MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY • GDI | DATA AS OF 19 OCT 2026

एशियन गेम में आईसीसी के चेयरपर्सन जय शाह का चीफ प्रोटोकोल ऑफीसर पेरिका सुरेश ने किया जोरदार स्वागत

स्वतंत्र सिंह भुल्लर नई दिल्ली परिवहन विशेष समाचार पत्र दैनिक

नई दिल्ली।

जापान के नागोया में आयोजित एशियन गेम्स 2026 में भारत की ओर से चीफ प्रोटोकोल ऑफीसर के रूप में पेरिकार सुरेश ने अपने शानदार नेतृत्व एवं प्रोत्साहन से भारतीय खिलाड़ियों में जोश भरने का काम किया। इस अवसर पर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल के चेयरपर्सन जय अमित शाह भी उपस्थित रहे। नागोया जापान में आयोजित भारत-पाकिस्तान के क्रिकेट मैच में जय शाह ने भाग लेकर खिलाड़ियों का हौसला अफजाई किया।

चीफ प्रोटोकोल ऑफीसर श्री सुरेश ने इस अवसर पर आईसीसी के चेयरपर्सन जय शाह का जोरदार स्वागत किया। पेरिका सुरेश ने कहा कि आईसीसी के चेयरपर्सन जय शाह के कुशल नेतृत्व में भारतीय क्रिकेट टीम और मजबूत हुई है। पेरिका सुरेश

सेपक टकराव फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रथम संयुक्त महासचिव एवं तेलंगाना सेपक टकराव फेडरेशन के अध्यक्ष भी हैं। उनके नेतृत्व में पुरुष सेपक टकराव गेम्स में भारत ने कस्य पदक जीतकर देश को गौरवान्वित किया है। उन्होंने भारतीय सेपक टकराव टीम के खिलाड़ियों को मेडल जीतने के लिए बधाई दी तथा कहा कि यह खेल भारत की सीमा रेखा को पार कर विदेश में भी लोकप्रिय हो रहा है और भारतीय सेपक टकराव टीम लगातार अपनी मजबूत पहचान बनती जा रही है।

जीवित्पुत्रिका पर्व पर संतान के रक्षार्थ माताओं ने की पूजा-अर्चना

रिपोर्ट डॉ दीपक कुमार घोष परिवहन विशेष खूटी

जीवित्पुत्रिका व्रत (जितिया/जितिया) बड़े ही श्रद्धा और धूमधाम से मनाया गया। पंडित जितेन्द्र पोंडे ने विधि-विधान से माताओं को पर्व की कथा सुनाई और पूजन कार्य सम्पन्न कराया। अनुष्ठान कराते पंडित जितेन्द्र ने कहा कि जितिया तीन दिन का पर्व है - पहला दिन नहाय-खाय, दूसरे दिन मुख्य निर्जला व्रत, तीसरे दिन को पारण के साथ पर्व का समापन होता है।

जितिया मातृत्व का सबसे कठिन व्रत है। इस व्रत में माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र, स्वास्थ्य और सुख-समृद्धि के लिए 24 से 36 घंटे का कठोर निर्जला उपवास रखती हैं। इस दौरान अन्न-जल का पूर्ण त्याग किया जाता है।

मुरहू के समाजसेवी डॉ धर्मेंद्र नाथ तिवारी ने कहा कि जितिया पर्व में मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से संतान पर आने वाले सभी संकट दूर होते हैं। महिलाओं द्वारा खूटी के करों रोड़, पिपरा टोली, खूटी टोला, मुरहू सहित आसपास ग्रामीण क्षेत्रों में जितिया वृक्ष तले पूजा विधिवत की गई।

गुरु अनुपजी ने कहा कि बंगाली परिवार की मातायें भी खासकर धनबाद, रांची, पंच परगना, पूर्वी-पश्चिम सिंहभूम में यह पर्व सदियों से करती आ रही है।

पूजा-अर्चना में काफी संख्या में उपस्थित महिलाओं ने अपनी संतानों के अच्छे स्वास्थ्य, लंबे जीवन और सुख-समृद्धि की कामना ईश्वर से की।

पुत्रों की दीर्घायु की कामना लेकर हजारों माताओं ने रखा निर्जला व्रत,पूजा-अर्चना के साथ सम्पन्न हुआ ऐतिहासिक मेला

सौ साल पुरानी परंपरा में आस्था का सेलाब,मीरापुर बसहीं का ऐतिहासिक जिउतिया मेला सम्पन्न रिपोर्ट संतोष कुमार सिंह परिवहन विशेष समाचार पत्र वाराणसी:

मीरापुर बसहीं चौराहा स्थित माँ लक्ष्मी मीरापुर बसहीं प्राचीन तालाब पर लगभग एक सदी से चली आ रही ऐतिहासिक जिउतिया मेले की परंपरा इस वर्ष भी श्रद्धा, आस्था और उल्लास के वातावरण में माताओं एवं बहनों की पूजा-अर्चना के साथ सकुशल सम्पन्न हुई। पुत्र की दीर्घायु और सुख-समृद्धि की कामना को लेकर महिलाओं ने कठिन निर्जला

जिउतिया व्रत रखा और विधि-विधान से पूजा-अर्चना की मीरापुर बसहीं स्थित प्राचीन तालाब परिसर में आयोजित इस मेले में आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। आयोजकों के अनुसार लगभग पांच से दस हजार महिलाओं ने तालाब पर पहुंचकर अपने पुत्रों की लंबी आयु की कामना की पूरे परिसर में धार्मिक आस्था और भक्ति का माहौल बना रहा।

मीरापुर बसहीं चौराहा स्थित चन्द्र वाटिका में मौड़िया से बातचीत करते हुए महादीप फाउंडेशन एवं चन्द्र वाटिका की प्रबंधक अधिवक्ता दीपा सिंह ने कहा कि जिउतिया पर्व

श्रद्धालुओं के लिए शुद्ध पेयजल, साफ-सफाई,तालाब की स्वच्छता,पूजा के लिए बैठने की व्यवस्था सहित अन्य आवश्यक सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा गया।

महादीप फाउंडेशन एवं चन्द्र वाटिका की ओर से मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए दुकानदारों एवं वाहनों के लिए निशुल्क स्टैंड की व्यवस्था भी की गई। इससे मेले में आने वाले लोगों को काफी सुविधा मिली और यातायात व्यवस्था को भी व्यवस्थित बनाए रखने में सहयोग मिला जिउतिया मेले को शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित ढंग से सम्पन्न कराने में माँ लक्ष्मी मीरापुर बसहीं प्राचीन तालाब ट्रस्ट के अध्यक्ष मनीष पटेल,मुकेश इंशरवाला,सरोज पटेल,संग्राम पटेल, स्थानीय पार्षद सहित क्षेत्र के नागरिकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

स्थानीय प्रशासन का भी आयोजन को सकुशल सम्पन्न कराने में सहयोग प्राप्त हुआ। आयोजकों ने कहा कि लगभग सौ वर्षों से चली आ रही यह परंपरा मीरापुर बसहीं की सांस्कृतिक एवं धार्मिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्षेत्रवासियों के सामूहिक सहयोग से हर वर्ष जिउतिया मेले का आयोजन श्रद्धा और सौहार्द के साथ किया जाता है।।

मिला,मोबाइल में उपलब्ध नंबर 9336087097 पर संपर्क कर पर्स मिलने की जानकारी दी गई। फोन पर बातचीत के दौरान अंकिता सिंह,पत्नी बृजेश कुमार सिंह निवासी ग्राम बीबा मऊ जनपद जौनपुर उत्तर प्रदेश ने पर्स अपना होना बताया। इसके बाद महिला के कैंट रोडवेज स्टेशन पहुंचने पर उनकी पहचान आधार कार्ड के माध्यम से सुनिश्चित की गई। पर्स में रखे सामान के संबंध में पूछताछ करने पर महिला द्वारा बताए गए सभी सामान सही पाए गए। पर्स में नकद 1,390 रुपये,लगभग 12 ग्राम वजन की एक सोने की चेन,एक चांदी की पायल तथा परिवार के सदस्यों के आधार कार्ड सहित अन्य आवश्यक सामान बरामद हुआ। सभी सामान की अनुमानित

कीमत करीब 1,50,000 रुपये (एक लाख पचास हजार रुपये) आंकी गई। आवश्यक सत्यापन एवं औपचारिकता पूरी करने के बाद सुरक्षा स्टाफ नागेंद्र चौबे की मौजूदगी में समझ गवाह सुपुर्दगी नामा तैयार कर बरामद सामान को उसकी वास्तविक स्वामिनी अंकिता सिंह को सुरक्षित सुपुर्द कर दिया गया। पर्स एवं उसमें रखे कीमती सामान को सुरक्षित वापस पाकर महिला ने रेलवे सुरक्षा बल के जवानों के प्रति आभार व्यक्त किया और उनकी ईमानदारी एवं तत्परता की खुले मन से प्रशंसा की। संयोग से जीवित्पुत्रिका (जिउतिया) व्रत के अवसर पर अपना जरूरी सामान वापस मिलने पर महिला ने इसे विशेष राहत एवं प्रसन्नता का विषय बताया।।

नशे से सियासत तक: पंजाब की एक कड़वी कहानी



डॉ. विजय गर्ग



माता-पिता अपनी जीवनभर की बचत इलाज पर खर्च कर सकते हैं। मां लगातार चिंता में रह सकती है। पिता आर्थिक और भावनात्मक दबाव महसूस कर सकता है। भाई-बहन भी इसके प्रभाव से अछूते नहीं रहते। यदि परिवार का कमाने वाला व्यक्ति नशे की लत का शिकार हो जाए, तो पूरे घर की आर्थिक स्थिरता प्रभावित हो सकती है।

जब कोई गंभीर सामाजिक समस्या राजनीति का विषय बनती है, तो एक खतरा यह भी होता है कि आम लोगों का दर्द राजनीतिक बहस के पीछे छिप जाए। इसलिए सबसे पहले इस समस्या को नारों से आगे बढ़कर समझने की आवश्यकता है।

माता-पिता अपनी जीवनभर की बचत इलाज पर खर्च कर सकते हैं। मां लगातार चिंता में रह सकती है। पिता आर्थिक और भावनात्मक दबाव महसूस कर सकता है। भाई-बहन भी इसके प्रभाव से अछूते नहीं रहते। यदि परिवार का कमाने वाला व्यक्ति नशे की लत का शिकार हो जाए, तो पूरे घर की आर्थिक स्थिरता प्रभावित हो सकती है।

कई बार कर्ज, घरेलू तनाव, सामाजिक अलगाव और रोजगार का नुकसान भी इस समस्या से जुड़ जाते हैं। इसलिए हर आंकड़े के पीछे एक मानवीय कहानी होती है।

स्वास्थ्य समस्या से राजनीतिक मुद्दे तक

नशे की समस्या मूल रूप से स्वास्थ्य और सामाजिक क्षेत्र से जुड़ी समस्या है, लेकिन पंजाब में यह एक महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दा भी बन चुकी है। विभिन्न सरकारों और राजनीतिक दलों ने नशा नियंत्रण, कानून लागू करने, उपचार, पुनर्वास और रोजगार जैसे विषयों पर अपने-अपने विचार रखे हैं।

चुनावों के दौरान नशे के प्रसार और सरकारों की कार्यप्रणाली को लेकर आरोप-प्रत्यारोप भी तेज हो सकते हैं। लोकतंत्र में ऐसी बहस स्वाभाविक है। लेकिन इस बहस के दौरान नशे से प्रभावित परिवारों का दर्द पीछे नहीं छूटना चाहिए।

किसी सरकार या नीति की प्रभावशीलता को केवल नारों से नहीं, बल्कि आंकड़ों, उपचार के परिणामों, तस्करी के विरुद्ध कार्रवाई, मामलों की जांच, पुनर्वास तथा स्वतंत्र मूल्यांकन जैसे

आत्मनिर्भरता या कर्ज का जाल? ग्रामीण महिला की कहानी

डॉ. विजय गर्ग

ग्रामीण महिला के जीवन में कर्ज कभी उम्मीद का दरवाजा खोलता है और कभी चिंता का कारण बन जाता है। पशु खरीदने, सिलाई का काम शुरू करने, छोटी दुकान खोलने, कृषि से जुड़ी गतिविधियां या परिवार की किसी तत्काल जरूरत को पूरा करने के लिए लिया गया छोटा ऋण उसे आय का स्रोत दे सकता है। लेकिन यदि ऋण उसकी आय पैदा करने की क्षमता से अधिक हो जाए या एक कर्ज की किस्त चुकाने के लिए दूसरा कर्ज लेना पड़े, तो यही ऋण आर्थिक बोझ बन सकता है।

इसलिए असली सवाल यह नहीं है कि कर्ज अच्छा है या बुरा। असली सवाल यह है कि क्या कर्ज ग्रामीण महिला को आत्मनिर्भर बना रहा है या उसे किस्तों और कर्ज के चक्र में फंसा रहा है?

कर्ज से आत्मनिर्भरता तक

जब किसी महिला को अपना छोटा व्यवसाय शुरू करने के लिए पूंजी मिलती है, तो कर्ज उसके लिए अवसर बन सकता है। वह दूध देने वाला पशु खरीद सकती है, सिलाई-कढ़ाई का काम शुरू कर सकती है, खाद्य पदार्थ बनाकर बेच सकती है या स्थानीय बाजार से जुड़ी कोई छोटी आय वाली गतिविधि शुरू कर सकती है।

यदि इस निवेश से नियमित आय पैदा होती है और किस्त आसानी से चुकाई जा सकती है, तो कर्ज आर्थिक सशक्तीकरण का साधन बन सकता है।

लेकिन केवल पैसा मिल जाना ही सशक्तीकरण नहीं है। यह भी महत्वपूर्ण है कि पैसे के उपयोग का निर्णय कौन करता है, आय पर नियंत्रण किसका है और ऋण चुकाने की जिम्मेदारी किस पर है।

जब छोटा कर्ज बड़ा बोझ बन जाता है

कई बार एक छोटी-सी किस्त शुरुआत में आसान लगती है। लेकिन यदि परिवार की आय अनियमित हो, फसल खराब हो जाए, व्यवसाय को अपेक्षित आमदनी न हो या अचानक कोई बड़ा

खर्च सामने आ जाए, तो किस्त चुकाना मुश्किल हो सकता है।

समस्या तब और गंभीर हो सकती है जब एक कर्ज की किस्त चुकाने के लिए दूसरा कर्ज लिया जाता है। इस तरह कर्ज की जरूरत धीरे-धीरे कर्ज पर निर्भरता में बदल सकती है।

कागज पर कर्ज छोटा हो सकता है, लेकिन कई कर्जों की किस्तें मिलकर परिवार के बजट पर बड़ा दबाव डाल सकती हैं।

कर्ज की छिपी हुई कीमत

कर्ज लेते समय केवल मिलने वाली राशि को देखना पर्याप्त नहीं है। यह समझना भी जरूरी है कि कुल कितनी राशि वापस करनी है, व्याज और अन्य खर्च कितने हैं, किस्त कितनी बार देनी है और भुगतान में देरी होने पर क्या परिणाम हो सकते हैं।

ग्रामीण महिला के लिए ये सवाल महत्वपूर्ण हैं:

- मुझे कुल कितनी राशि उधार ले रही हूं?
- मुझे कुल कितनी राशि वापस करनी होगी?
- व्याज और अन्य शुल्क कितने हैं?
- किस्त साप्ताहिक, मासिक या किसी अन्य अंतराल पर देनी है?
- यदि कुछ समय के लिए आय कम हो जाए तो क्या होगा?
- क्या मेरी आय किस्त के साथ-साथ घरेलू खर्च भी संभाल सकती है?
- इन सवालों की जानकारी के बिना लिया गया कर्ज आर्थिक जोखिम बढ़ा सकता है।

स्वयं सहायता समूहों की भूमिका

ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूहों ने महिलाओं को बचत, सामूहिक जिम्मेदारी और वित्तीय गतिविधियों से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सामूहिक बचत महिलाओं में वित्तीय अनुशासन और आपसी सहयोग को बढ़ावा दे सकती है।

लेकिन केवल समूह का सदस्य बन जाना अपने आप में आर्थिक सशक्तीकरण की गारंटी



नहीं है। यदि ऋण के उपयोग, भुगतान और आय पैदा करने के बारे में सही समझ न हो, तो सामूहिक ऋण भी व्यक्तिगत वित्तीय दबाव का कारण बन सकता है।

इसलिए स्वयं सहायता समूहों के साथ वित्तीय साक्षरता, व्यावसायिक कौशल और बाजार से जुड़ाव भी जरूरी है।

कर्ज किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है?

हर कर्ज एक जैसा नहीं होता। यदि कर्ज से ऐसा साधन खरीदा जाता है जो भविष्य में आय पैदा करता है, तो उसकी उपयोगिता अलग होती है। लेकिन यदि कर्ज केवल पुराने कर्ज की किस्त, रोजमर्रा के खर्च या लगातार बढ़ती जरूरतों को पूरा करने में इस्तेमाल हो रहा है, तो वित्तीय

वास्तविक सशक्तीकरण तब है जब महिला को पैसे के बारे में निर्णय लेने, आय अर्जित करने, बचत करने और अपने भविष्य की योजना बनाने का अधिकार और क्षमता हो।

कर्ज के साथ कौशल भी जरूरी

केवल कर्ज देने से ग्रामीण गरीबी का स्थायी समाधान नहीं निकल सकता। कर्ज के साथ कौशल, तकनीकी ज्ञान, बाजार तक पहुंच, उत्पाद की बिक्री, डिजिटल साक्षरता और व्यावसायिक मार्गदर्शन भी आवश्यक हैं।

किसी महिला को सिलाई मशीन देने से अधिक महत्वपूर्ण यह भी है कि उसे सिलाई का कौशल, ग्राहक तक पहुंच, उत्पाद की कीमत तय करने की समझ और ऑनलाइन या स्थानीय बाजार में बिक्री के अवसर मिलें।

इसलिए एक प्रभावी मॉडल हो सकता है: बचत + जिम्मेदार कर्ज + कौशल + बीमा + बाजार + वित्तीय साक्षरता।

वित्तीय संस्थाओं की जिम्मेदारी

बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के लिए भी यह जरूरी है कि कर्ज की शर्तें सरल और पारदर्शी भाषा में समझाई जाएं। ग्राहक को केवल कर्ज देना ही उद्देश्य न हो, बल्कि उसकी भुगतान क्षमता को भी ध्यान में रखा जाए।

महिलाओं के लिए वित्तीय सलाह, कर्ज प्रबंधन और छोटे व्यवसाय से जुड़ी प्रशिक्षण व्यवस्था उन्हें बेहतर निर्णय लेने में मदद कर सकती है।

कर्ज का मानसिक बोझ

कर्ज केवल आर्थिक मामला नहीं है। लगातार किस्तों की चिंता पारिवारिक तनाव, असुरक्षा और भविष्य को लेकर चिंता का कारण बन सकती है। इसलिए कर्ज की सफलता को केवल इस आधार पर नहीं मापना चाहिए कि कितने लोगों को कर्ज दिया गया। यह भी देखना चाहिए कि कर्ज ने उनकी आय, बचत, संपत्ति और आर्थिक सुरक्षा में कितना सुधार किया।

कर्जदार से उद्यमी तक

ग्रामीण महिला के लिए सबसे बड़ा बदलाव तब आ सकता है जब वह केवल कर्ज लेने वाली न रहकर अपनी आय पैदा करने वाली उद्यमी बने।

मंजिल यह नहीं होनी चाहिए कि महिला लगातार नए कर्ज लेती रहे। मंजिल यह होनी चाहिए कि वह: कर्ज लेने से कमाई की ओर, कमाई से बचत की ओर, बचत से संपत्ति की ओर, और संपत्ति से आर्थिक सुरक्षा की ओर बढ़े।

निष्कर्ष

कर्ज अपने आप में न तो आत्मनिर्भरता है और न ही कर्ज का जाल। इसका प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि कर्ज क्यों लिया गया, कैसे इस्तेमाल किया गया, उससे कितनी आय पैदा हुई और उसकी वापसी की क्षमता कितनी है।

वास्तविक महिला सशक्तीकरण का अर्थ केवल उसके नाम पर कर्ज होना नहीं है। इसका अर्थ है—अपनी आय, अपने पैसे, अपनी बचत और अपने आर्थिक फैसलों पर अधिकतम नियंत्रण।

ग्रामीण महिला को केवल कर्जदार नहीं, बल्कि कमाने वाली, बचत करने वाली, संपत्ति बनाने वाली और अपने भविष्य का निर्णय लेने वाली आर्थिक रूप से मजबूत नागरिक बनाना ही वास्तविक लक्ष्य होना चाहिए।

डॉ. विजय गर्ग सेवानिवृत्त प्राचार्य। प्रख्यात वैज्ञानिक स्ट्रीट कोर चंद, एमएचआर, मलोट, पंजाब — 152107



कानून का प्रभावी क्रियान्वयन भी महत्वपूर्ण है।

अवैध नशीली दवाओं की आपूर्ति आपराधिक नेटवर्क से जुड़ी हो सकती है। इसलिए प्रभावी जांच, खुफिया जानकारी, वित्तीय लेन-देन की जांच, विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय और कानूनी कार्रवाई आवश्यक है।

लेकिन तस्करी से लाभ कमाने वाले लोगों और नशे की लत से जुड़ा रहे व्यक्तियों के बीच अंतर करना भी महत्वपूर्ण है।

तस्करी के खिलाफ प्रभावी कानूनी कार्रवाई और नशे से प्रभावित लोगों के लिए उपचार—दोनों साथ-साथ चल सकते हैं।

पुनर्वास ही अंत नहीं

किसी व्यक्ति को पुनर्वास केंद्र भेज देना यात्रा का अंत नहीं है। उपचार के बाद भी दोबारा नशे की ओर लौटने की संभावना हो सकती है। यदि व्यक्ति उसी वातावरण, बेरोजगारी, गलत संगति या सामाजिक दबाव में वापस चला जाता है, तो कठिनाइयां फिर उत्पन्न हो सकती हैं।

इसलिए पुनर्वास में उपचार के साथ निरंतर काउंसलिंग, पारिवारिक सहयोग, शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के अवसर भी शामिल होने चाहिए।

पुनर्वास की वास्तविक सफलता केवल इस बात से नहीं मापी जानी चाहिए कि कितने लोग उपचार के लिए पहुंचे, बल्कि इस बात से भी कि कितने लोग स्थिर और उत्पादक जीवन की ओर लौट सके।

पंजाब को दीर्घकालिक रणनीति चाहिए

नशे की समस्या किसी एक अभियान, एक सरकार या एक विभाग से हल नहीं हो

बेठे के घर लौटने की प्रतीक्षा करती है।

यह उस पिता की कहानी है जो अपने बच्चे के उपचार के लिए अपनी बचत खर्च कर देता है।

यह उस बहन की चिंता है जो अपने भाई का भविष्य बचाना चाहती है।

यह उस युवा की कहानी है जिसके अपने सपने थे, लेकिन जो नशे की लत में फंस गया।

और यह उन परिवारों की कहानी भी है जिन्होंने चुपचाप अपने प्रियजनों का साथ दिया और उन्हें फिर से सामान्य जीवन की ओर लाने का प्रयास किया।

ये कहानियां हमेशा समाचारों की सुर्खियां नहीं बनतीं, लेकिन यही पंजाब की वास्तविक मानवीय तस्वीर है।

पंजाब का भविष्य

राजनीतिक नेतृत्व का महत्व केवल चुनावों के दौरान किए गए वादों में नहीं, बल्कि उन संस्थाओं के निर्माण में भी है जो लंबे समय तक समाज को मजबूत बनाती हैं।

एक ऐसे पंजाब की कल्पना कीजिए जहां हर जिले में सुलभ उपचार सुविधाएं हों, हर स्कूल में प्रभावी जागरूकता कार्यक्रम हों, युवाओं के लिए खेल और कौशल विकास के अवसर हों, परिवार बिना झिझक सहायता ले सकें, तस्करी नेटवर्क के खिलाफ प्रभावी जांच हो और पुनर्वास के बाद युवाओं को शिक्षा और रोजगार से जोड़ा जा सके।

ऐसा परिवर्तन किसी भी राजनीतिक नारे से अधिक महत्वपूर्ण होगा।

पंजाब का भविष्य केवल इस बात से नहीं मापा जाना चाहिए कि कितने लोग नशे की लत में फंसे हैं। इसे इस बात से भी मापा जाना चाहिए कि कितने लोगों को नशे से बाहर निकलने, अपना जीवन फिर से बनाने और अपने सपनों को पूरा करने में सहायता मिली।

नशे और सियासत की यह कड़वी कहानी एक नई कहानी में बदल सकती है—रोकथाम, जवाबदेही, उपचार, पुनर्वास, शिक्षा और नए अवसरों की कहानी।

पंजाब ने अपने इतिहास में अनेक चुनौतियों का सामना किया है। इसकी सबसे बड़ी ताकत हमेशा इसके लोग रहे हैं।

आज की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि हमारी युवा पीढ़ी को नशे और राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप की विरासत न मिले, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, आत्मविश्वास, अवसर और एक बेहतर भविष्य मिले।

नशे के खिलाफ लड़ाई अंततः राजनीति से बड़ी होनी चाहिए। यह मानव जीवन, सम्मान और पंजाब के भविष्य के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी बननी चाहिए।

डॉ. विजय गर्ग रिटायर्ड प्रिंसिपल। एमिनेंट साइटिस्ट स्ट्रीट कोर चंद, मलोट, पंजाब — 152107

झारखंड हाईकोर्ट ने दाखिले की विदेशी छात्रवृत्ति रोकने पर कड़ी आपत्ति जताई

आईर : पांच अक्टूबर तक आवेदक को रु 39,76,665 अदा करें
अन्यथा छह अक्टूबर को निदेशक शरीर उपस्थित हों

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड झारखंड

रांची, झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने यूनाइटेड किंगडम (यूके) की यूनिवर्सिटी आफ साउथेम्प्टन में दाखिले के लिए चयनित मेधावी छात्र को स्वीकृति के बाद छात्रवृत्ति की राशि जारी नहीं किए जाने पर कड़ी नाराजगी जताई है।

अदालत ने झारखंड स्टेट हायर एजुकेशन कार्डसिल के कार्यकारी निदेशक को निर्देश दिया है कि छात्र को 39,76,655.20 रुपये की पूरी छात्रवृत्ति राशि पांच अक्टूबर तक हर हाल में जारी करें।

राशि जारी नहीं होने की स्थिति में कार्यकारी निदेशक को छह अक्टूबर को अदालत में सशरीर उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देना होगा। रांची के कांके निवासी सनत झा की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है।

प्रार्थी के अधिवक्ता ने अदालत को



बताया कि सनत झा का चयन यूनिवर्सिटी आफ साउथेम्प्टन में तीन वर्षीय बीटेक साफ्टवेयर इंजीनियरिंग (कंप्यूटर साइंस एंड इंफार्मेशन सिस्टम) पाठ्यक्रम के लिए हुआ है। छात्र ने राज्य सरकार के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की ओर से नौ जुलाई 2024 को जारी संकल्प के तहत

छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया था। अदालत को बताया गया कि छात्र की पात्रता पर विचार करने के बाद झारखंड स्टेट हायर एजुकेशन कार्डसिल के कार्यकारी निदेशक ने नौ सितंबर को छात्रवृत्ति की स्वीकृति प्रदान की। इसी दिन छात्रवृत्ति की 39,76,655.20 रुपये की राशि जारी

करने का पत्र भी जारी किया गया था। इसके बाद छात्र को अब तक राशि उपलब्ध नहीं कराई गई। अदालत को बताया गया कि विश्वविद्यालय में फीस जमा करने की अंतिम तिथि पहले 21 सितंबर निर्धारित थी। छात्र के अनुरोध पर इसे बढ़ाकर पांच अक्टूबर कर दिया गया है।

छात्र लगातार संबंधित अधिकारियों से छात्रवृत्ति की राशि जारी करने का अनुरोध करता रहा, लेकिन भुगतान नहीं किया गया। फीस जमा नहीं होने की स्थिति में उसका विदेश स्थित विश्वविद्यालय में दाखिला प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए उसे हाई कोर्ट का रुख करना पड़ा।

अदालत ने आदेश में कहा कि यह गंभीर चिंता का विषय है कि संबंधित प्रतिवादी एक मेधावी छात्र के करियर के प्रति पूरी तरह असंवेदनशील बना हुआ है।

ऐसी असंवेदनशीलता न केवल छात्र के उज्ज्वल करियर को प्रभावित कर सकती है, बल्कि राज्य सरकार की उस कल्याणकारी नीति के उद्देश्य को भी विफल कर सकती है, जिसके तहत मेधावी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया जाना है।

कक्षा चल रही थी, तभी पीएम श्री स्कूल छत से गिरा कंक्रीट, आठवीं कक्षा का छात्र घायल



मनोरंजन शासमल, स्टेट हेड ओडिशा

भुवनेश्वर/चित्रकोंडा: कक्षा चलने के दौरान स्कूल की छत से कंक्रीट का एक हिस्सा गिरने से आठवीं कक्षा का एक छात्र घायल हो गया। यह घटना चित्रकोंडा पीएम श्री उच्चमाध्यमिक विद्यालय में हुई। जानकारी के अनुसार, विद्यालय में पढ़ाई चल रही थी। इसी दौरान अचानक छत से कंक्रीट का एक हिस्सा टूटकर आठवीं कक्षा के छात्र सुरेश कुंडाल के ऊपर गिर पड़ा। इससे छात्र के सिर में गंभीर चोट लगी। बताया गया है कि घायल छात्र के सिर में पांच टांके लगाए गए हैं। घटना के बाद घायल छात्र को तत्काल

चित्रकोंडा उपखंड चिकित्सालय ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। प्रधानाध्यापिका जानकी हंताल ने बताया कि छत से कंक्रीट गिरने के कारण सुरेश कुंडाल के सिर में पांच टांके लगे हैं। डॉक्टरों ने बताया है कि छात्र को फिलहाल किसी तरह का खतरा नहीं है। कक्षा में पढ़ाई के दौरान इस तरह की घटना होने से छात्रों और अभिभावकों में चिंता जताई गई है। विद्यालय भवन की सुरक्षा और छत की स्थिति की जांच करने तथा भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने की मांग की गई है।

सिमडेगा की तीन बेटियों ने देश के माथे सजाया स्वर्ण तिलक :कंचन सिंह, डीसी

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड -झारखंड

रांची , झारखंड के सिमडेगा जिले की उपायुक्त कंचन सिंह ने एक पोस्ट शेयर की है जिसमें बधाई के दौरान एक खिलाड़ी की मां भावुक हो गयी और खुशी के आंसू निकलते नजर आये। यद्यपि जापान में चल रहे एशियाई खेलों में सिमडेगा की तीन एवं खूंटी की एक बेटी ने झारखंड का भाषा ऊंचा किया है। खूंटी से निक्की प्रधान भी महिला हाकी में चीन को पछाड़ने में आगे रही है।

उपायुक्त कंचन सिंह ने लिखा कहा है आज पूरा हिंदुस्तान खुशी से झूम रहा है और सिमडेगा का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। हमारी बेटियों ने वह कर दिखाया है जिसका इंतजार भारत को पिछले 44 सालों से था। भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशियाई खेलों के फाइनल में चीन को 1-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। 1982 के बाद पहली बार यह चमचमता स्वर्ण पदक भारत की झोली में गिरा है। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे खूबसूरत और दिल छू लेने वाला हिस्सा यह है कि इस ऐतिहासिक जीत की पटकथा किसी बड़े महानगर के आलीशान खेल परिसर में नहीं बल्कि हमारे अपने सिमडेगा की



लाल मिट्टी और धूल भरे मैदानों पर लिखी गई है। भारतीय टीम की कप्तान हमारे सिमडेगा के बड़कीछापर की बेटी सलीमा टेटे के मजबूत हाथों में

थी। उनके साथ मैदान पर ढाल बनकर खड़ी थीं जिले की दो और लाडलियां दीपिका सोरेंग और ब्यूटी डुंगडुंग। जब फाइनल मैच का समय पूरा हुआ



और भारत की जीत तय हुई तो सिमडेगा में ढोल की थाप गूंज उठी। लोग खुशी से नाचने लगे। एक-दूसरे को मिठाई खिलाई। एक जिले के मुखिया के तौर पर यह खुशी और गर्व शब्दों में बयान करना मुश्किल है। एक उपायुक्त होने के नाते जब मैं अपने जिले के लोगों के चेहरों पर यह गर्व देखती हूँ तो मेरा दिल भी खुशी से भर जाता है।

देश भर में हमारे सिमडेगा को ‘हॉकी की नर्सरी’ कहा जाता है। इसके पीछे हमारे सिमडेगा के खिलाड़ियों और बच्चों का जुनून है। सिमडेगा में बच्चे शायद चलना बाद में और हाथ में हॉकी स्टिक थामना पहले सीख लेते हैं। यहाँ हॉकी सिर्फ खेल नहीं है, एक सांस है। एक धड़कन है। जीने का तरीका है। बड़े शहरों में बच्चे जब वीडियो गेम और मोबाइल स्क्रीन से चिपके होते हैं, तब हमारे सिमडेगा के गांवों में सात-आठ साल के बच्चे जंगल से बांस काटते हैं और उसे खुद अपनी हॉकी स्टिक बनाते हैं। सरीफ़े के फल को गंद बनाकर उस गंद के पीछे नंगे पैर दौड़ते बच्चों की टोली आपको यहाँ के हर मोड़ पर मिल जाएगी। न महंगे जूते, न कोई चमचमता टर्फ वाला मैदान, न कोई महंगी डाइट। बस खाली पड़े खेत में दो पथर रखकर गोलपोस्ट बना लेते हैं और शुरू हो जाता है मैच। सुबह की पहली किरण से लेकर शाम को सूरज ढलने तक, गंद की खट-खट की आवाज यहाँ की आबोवाह में संगीत की तरह बहती है। खेल के प्रति यह जो पागलपन और अटूट प्यार है वही सिमडेगा की असली ताकत है और जब इसी लगन को सही दिशा

मिल जाती है, तो यह सुनहरा क्षण आता है, और माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन जी के नेतृत्व में राज्य सरकार लगातार इसके अवसर प्रदान कर रही है। मैदान पर तिरंग लहराने वाली हमारी इन तीनों बेटियों की कहानी किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं है। इनकी जीत जितनी बड़ी है, इनका संघर्ष उससे भी कहीं ज्यादा बड़ा रहा है। पर अपनी जी-तोड़ मेहनत से इन्होंने भारतीय टीम में अपनी जगह पक्की कर ली। सिमडेगा की उपायुक्त के रूप में मैं अपनी तीनों लाडलियों और पूरी भारतीय टीम को दिल की गहराइयों से बधाई देती हूँ। इन बेटियों ने साबित कर दिया है कि गरीबी और मुश्किलें कभी हौसलों के आगे टिक नहीं सकती। सलीमा, दीपिका और ब्यूटी की यह सफलता सिमडेगा के हजारों युवा खिलाड़ियों के लिए नई प्रेरणा बनेगी। हमारी बेटियों ने इतिहास रच दिया है और सिमडेगा हमेशा अपनी इन बेटियों के साथ खड़ा रहेगा। निक्की प्रधान खूंटी की है उपायुक्त खूंटी का बंधाई एवं प्रतिक्रिया कैसा होगा निक्की के लिए देखना लाजमी होगा।

जमीन दाखिल खारीज में बुढ़मू सीओ के खिलाफ चौंकाने वाला तथ्य, ढांचा तैयार कर पैसे वसूले जाते थे

बढ़मू में एसीबी तो अनेकों सीओ के कार्य शैली एवं रिकार्ड रूम के दस्तावेज सुरक्षित नहीं, बड़ी एजेंसियों के राडार पर कोल्हान !

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड -झारखंड

रांची , रांची के अनेक भ्रष्ट सीओ समेत बुढ़मू अंचल के तत्कालीन अंचलाधिकारी सच्चिदानंद कुमार वर्मा के भ्रष्टाचार और अवैध वसूली के सिंडिकेट की परतें अब भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की जांच में आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगी हैं. दाखिल-खारिज के नाम पर घूसखोरी के मामले में फिलहाल जेल में बंद पूर्व सीओ के खिलाफ एसीबी को कई चौंकाने वाले और पुख्ता साक्ष्य हाथ लगे हैं. जांच में यह साफ हुआ है कि अंचल कार्यालय में नियमों की धज्जियां उड़ाकर पैसों के दम पर जमीनों का म्यूटेशन करने का एक पूरा संगठित ढांचा तैयार किया गया था. एसीबी की तफ्तीश में पूर्व सीओ का रिश्तत वसूलने का बेहद सुनियोजित और शांतिर तरीका उजागर हुआ है. वे पहले आम रैयतों के म्यूटेशन आवेदननों में जानबूझकर तकनीकी खामियां निकालकर या बेतुके आधार पर उन्हें निरस्त (रद्द) कर देते थे. इसके बाद जब परेशान आवेदक मजबूर होकर दलालों और बिचौलियों के नेटवर्क तक पहुंचता था, तो पैसों का सौदा तय होते ही महज 24 घंटे या चंद दिनों के भीतर वही खारिज आवेदन अचानक मंजूर कर लिया जाता था. एसीबी को जांच के दौरान ऐसे 17 संदिग्ध मामलों के पुख्ता दस्तावेज मिले हैं, जिनमें घूस की रकम मिलते ही पूर्व में निरस्त किए गए म्यूटेशन को तुरंत हरी झंडी दे दी गई थी. इस बड़े सिंडिकेट को बेनकाब करने के लिए एसीबी के एक अधिकारी ने भेष



बदलकर अंचल कार्यालय की रेकी की थी. मामले की शुरुआत तब हुई जब शिकायतकर्ता सुबोध कुमार जमीन म्यूटेशन के लिए सीओ से मिले, जिन्होंने उन्हें राजस्व उप-निरीक्षक राजेश किशोर रवि के पास भेज दिया. घूस मांगने की पुष्टि होने पर एसीबी ने जाल बिछाया और राजेश के भाई गौतम कुमार को 10 हजार रुपये की रिश्तत लेते रहेगाथ दबोच लिया. जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि घूस केवल नकद ही नहीं, बल्कि डिजिटल माध्यमों से भी ली जाती थी. बैंक रिकॉर्ड्स और गवाहों के बयानों से साफ हुआ कि यूपीआई के जरिए रिश्तत का पैसा राजस्व उप-निरीक्षक के परिजनों के बैंक खातों में ट्रांसफर कराया जाता था. एसीबी की तफ्तीश में पूर्व सीओ का रिश्तत वसूलने का बेहद सुनियोजित और शांतिर तरीका उजागर हुआ है. वे पहले आम रैयतों के म्यूटेशन आवेदननों में जानबूझकर तकनीकी खामियां निकालकर या बेतुके आधार पर उन्हें

निरस्त (रद्द) कर देते थे. इसके बाद जब परेशान आवेदक मजबूर होकर दलालों और बिचौलियों के नेटवर्क तक पहुंचता था, तो पैसों का सौदा तय होते ही महज 24 घंटे या चंद दिनों के भीतर वही खारिज आवेदन अचानक मंजूर कर लिया जाता था. एसीबी को जांच के दौरान ऐसे 17 संदिग्ध मामलों के पुख्ता दस्तावेज मिले हैं, जिनमें घूस की रकम मिलते ही पूर्व में निरस्त किए गए म्यूटेशन को तुरंत हरी झंडी दे दी गई थी. इस बड़े सिंडिकेट को बेनकाब करने के लिए एसीबी के एक अधिकारी ने भेष बदलकर अंचल कार्यालय की रेकी की थी. मामले की शुरुआत तब हुई जब शिकायतकर्ता सुबोध कुमार जमीन म्यूटेशन के लिए सीओ से मिले, जिन्होंने उन्हें राजस्व उप-निरीक्षक राजेश किशोर रवि के पास भेज दिया. घूस मांगने की पुष्टि होने पर एसीबी ने जाल बिछाया और राजेश के भाई गौतम कुमार को 10 हजार रुपये की रिश्तत लेते रहेगाथ दबोच लिया. जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि घूस केवल नकद ही नहीं, बल्कि डिजिटल माध्यमों से भी ली जाती थी. बैंक रिकॉर्ड्स और गवाहों के बयानों से साफ हुआ कि यूपीआई के जरिए रिश्तत का पैसा राजस्व उप-निरीक्षक के परिजनों के बैंक खातों में ट्रांसफर कराया जाता था. कोल्हान के अनेक सीओ के कार्यालय में रखे जमीन दस्तावेज एवं उनपर हो रहे अनैतिक कार्यों पर झूठे जमीन दलाल, कारोबारियों पर नजर पड़ने जा रही है. बड़ी एजेंसियों की कान में सुबुगवाहट शुरू हो गयी है, जिसमे बड़ी मछलियां फंस सकती है

सरायकेला मे सोलह दिनात्मक तांत्रिक दुर्गा पूजा आज से गवर्नर जनरल के उस मार्जार एग्रीमेंट के वनिस्पत परंपरा उपेक्षित

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड झारखंड

ऐतिहासिक शहर सरायकेला की सोलह दिनात्मक दुर्गा पूजा उस सोलह दिनात्मक समारोह की है जो शारदीय नवरात्र नहीं अपितु एक पक्ष तक मनाता है। यही तांत्रिक मान्यता समूचे उत्कल प्रदेश में व्याप्त है। अन्यत्र नवरात्र का नौ दिनों की पूजा विगत पंद्रह-बीस वर्षों में प्रचलन हुआ यहां बढ़ा है वह कदाचित नहीं सोलह दिनात्मक सोलह पूजा इस माटी का तांत्रिक पद्धति नहीं। जिसको लेकर गवर्नर जनरल एवं राजा सरायकेला के बीच हुए उस मार्जार एग्रीमेंट कुछ कहता है, जबकि यहां प्रशासनिक गतिविधि में कुछ और होता आया है। यहां बताया उचित होगा कि कोई बाला तब तक मां नहीं बनती जब वह सही उम्र पर पितृ संसर्ग में मां बनने लायक नहीं हो जाती एवं उसे प्रदत्त सारे शस्त्रों की सही संचालन हेतु मानसिक व शारिरिक रूप में सक्षम नहीं मानी जाती। यही कारण दुर्गा युद्ध की देवी ठहरी। अतः सोलह दिनों का पितृ पक्ष एवं मातृ पक्ष स्पर्श से 16 दिनात्मक पूजा समूचे उत्कल देशी रियासतों की आज भी पूजा है। नौ दिन तक बालिका पूजन नवरात्र नहीं होता किसी भी उत्कललीय देशी रियासत के देवियों के समक्ष उसकी तांत्रिक परम्परा अनुचार ही दुर्गा पूजा 16 दिनों तक चलता। कारण उप प्रथम दुर्गा पूजा परम्परा मैसूर में बंगाल से जाकर बसे राजाओं द्वारा नहीं बल्कि ओडिशा से प्रारंभ हुआ था, जिसका इतिहास हमें उत्कल के 'आ गागा गोदावरी' भूखंड एवं वीरों की इतिहास बहुत कुछ गवाह देता है। उस मैसूर एवं तमाम ओडिशा के विभिन्न क्षेत्रों में सोलह दिनों का दशहरा आज भी ओडिशा की भांती मनाता है। इतिहास गवाह है, दशहरा सबसे पहले ईसापूर्व 300 ई में पुरी में प्रारंभ हुआ था, वहां के परमार राजाओं के समय।

जब मां दुर्गा महिषासुर वध की तो एही व्याख्या करता हमारा दूर्गा शप्तशति या चंडी पुराण मार्कंडेय ऋषि कृत। दुर्गा को सभी देवताओं ने शस्त्र अर्पित किये थे, सारे आयुधों का सही संचालन निमित्त एक बालिका उम्र का होना लाजिमी नहीं बनता था। सरायकेला की इस पुरानी स्व कन्हई महाराणा की प्रतिमा में जाएं देखें जहां उम्र सोलह साल की दिख रही है, वीरांगना मां दुर्गा। जोश भरी आंखों से वीर रस का वर्षा तो होट से वात्सल्यता की ममता। भक्तों यानी उनके सभी पुत्र-कन्याओं के ऊपर। यहां तो बाजे भी चार कलिल से ले जाकर सोलह कली तक बजते-मात्राओं के तेज बजते उतरते उसके समक्ष, जो विशुद्ध भारतीय शास्त्रीय धुन पर पर आधारित होता है। यही वजह रही है की सरायकेला देश-दुनियां के कला पटल पर शदियों से चर्चा का विषय रहा है चाहे यूरोप हो चाहे अमेरिका, चाहे पूजा-अर्चना हो या कलात्मक युद्ध छावनी आया छऊ (नृत्य) की ज्ञान गांगा। इस ज्ञान की गहरी समंदर में मोती ढुंढ पाना आसान काम नहीं। पुरखों के इसी सरायकेला के ज्ञानी पुरुष एक एक कर छोड़ चले गये काफी पहले, सरायकेला की उजड़ें विरासत संभालने में अब लोग कमजोर पड़ रहे हैं। आधुनिक लोकतंत्र के मकड़े जाल में फंसे अपनी आंखों से इतिहास खोते नजर आ रहे हैं। सच तो यहाँ किसी भी सरकार मे सही मायने में सरायकेला के लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं होना बड़ी बात है। कुली से कलेक्टर, संतरी से सचिव तक बाहरी (जिसकी कला-संस्कृति, आध्यात्म उनकी दृष्टिकोण से सब अलग परिवेश समुदाय के आते रहे हैं) विरासत को समझ पाने के लिए सदैव कम पड़ते, पर सभी के हर्ता-कर्ता और विधाता वे ही आज। सच पुछें तो आज जरूरत है सरायकेला के गूढ़ रहस्य को जानने, समझने, क्रियान्वयन करने एवं कराने की प्रतिकुल परिस्थिति में स्वयं



को जीदा रखने की लड़ रहे हैं यहां के परंपरा को लेकर चलने वाले लोग। सच तो यह है कि उस दुर्गा की अनेकों वाणी आदि वेद ऋग्वेद की अनेक ऋचाओं से आया है। प्रातः स्मरणीय मार्कंडेय ऋषि द्वारा रचित दुर्गा शप्तशती में कहा गया है आदि वेद के 10वें मंडल में यहां आगे आप कहती है:- राहमेव स्वयमिदं वदामि जुष्टं देवेभिरुत मानुषेभिः। यं कामयेतं तत्सुप्र कृणोमि तं ब्रह्माणं तमुषिं तं सुमेधाम्। इ

अर्थात् :- मैं स्वयं ही उस ब्रह्मात्मक तत्त्व का उपदेश करती हूँ जिसका सेवन देवताओं और मनुष्यों ने भी किया है। मैं स्वयं ब्रह्मा हूँ। मैं जिसे चाहती हूँ रक्षा करती हूँ, जिसे चाहती हूँ सर्वश्रेष्ठ बना देती हूँ, जिसे चाहती हूँ सुष्टि कर्ता ब्रह्मा बना देती, जिसे चाहती हूँ उसे मेधा युक्त मानव, गुरु के समान ज्ञानवान बना देती हूँ। ये हैं दुर्गा दुर्गाति नाशिनी वाणी जहां आज राजपाट भारतीय अधिराज्य में दान कर अपनी परंपरा बचाने की जिम्मेदारी हेतु एकत्रित हो जाते हैं 16 दिनों की पब्लिक दुर्गा पूजा में नगरवासी।